

## ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग का वसितार

### प्रलिस के ललतः

अन्य पछिडा वर्ग का आरक्षण, राषुद्रीय पछिडा वर्ग आयोग ।

### मेनुस के ललतः

उप-वर्गीकरण आयोग और उसके उददेश्य ।

## चरुा में कुतुतु?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रमिडल ने नुयायमूरुतु रोहणी आयोग को [अन्य पछिडा वर्ग \(OBC\) के उप-वर्गीकरण](#) की ऑऑ करने और 31 जनवरी, 2023 तक अपनी रपुऑरुत प्रसुतुत करने के ललतः 13वुतु वसितार दलतः है ।

- आयोग की रपुऑरुत प्रसुतुत करने की प्रारंभक समय-सीमा 12 सप्तःह थी (2 जनवरी, 2018 तक) ।

## प्रमुख बढु

### आयोग:

- 2 अकुतुबर, 2017 को राषुद्रेपतु के अनुडुदन के उपरंत संवधःन के अनुऑऑेद 340 के तहत गठतः इस आयोग को रोहणी आयोग (Rohini Commission) भी कहा जाता है ।
- इसे अन्य पछिडा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण और उनके ललतः आरकुषतः लःभुतु के समःन वतःरण का काम सुतुपा गया थः ।
  - वर्ष 2015 में [राषुद्रीय पछिडा वर्ग आयोग](#) (National Commission for Backward Classes- NCBC) ने सफःारशः की थी कु OBC को अतुतुत पछिडे वर्गुतु, अधकः पछिडे वर्गुतु और पछिडे वर्गुतु के रूड में वर्गीकृत कतःया जानः ऑःहःतः ।
  - NCBC के पास सामःजकः और शुकुषकः रूड से पछिडे वर्गुतु के संबध में शकःतुतुतु व कलुतुतुणकःरुतु उडःतुतुतु की ऑऑ करने का अधकःरः है ।

### आयोग के वऑःरःरुथ वषःतः:

- केंद्रीय OBC सूऑी में वभःनःन जातुतुतुतु के बीऑ आरकुषण लःभुतु के असमःन वतःरण की ऑऑ करना ।
- अन्य पछिडा वर्गुतु के मधुतु उप-वर्गीकरण के ललतः वैऑऑःनकः दृषुऑकुषण में तंतुतु, मःनदंड तैतुतुार करना ।
- वुतुतुतु डेटः कवरेऑ हेतु संबधतः जातुतुतुतु/सडुदःतुतुतु/उड-जातुतुतुतु/समःनःरुथक की पहऑःन करने का प्रुतुतुतु करना ।
- कःसुतुी भी प्रकःर के दुहरःव, असुडषुऑतुतु, वसःंगतुतुतुतु और वरुतुनी तः प्रतलःखन की तुरुऑतुतुतु का अधुतुतुतु एवं सुधःर की सफःारशः करना ।

### वरुतुतुतुतु प्रगतः:

- आयोग रःऑुतु सरकःरुतु, रःऑुतु पछिडा वर्ग आयोगुतु, सामुदःतुतु संघुतु आदः के प्रुतुनःधःतुतुतु के मधुतु प्रसुडुतु समनुवुतु करतः है । इसके अलःवः उऑऑ शकुषण संसुतुःनःतु और केंद्रीय वभःगुतु, सःरुवऑनकः कुषुतुतु के डुकुतुतु तथा वतुतुतुतु संसुतुःनःतु में डरुतुी हुने वःले [OBC के जातुतु-आधःरःतु ऑऑऑुतु](#) का संकलन करतः है ।
- वर्ष 2021 में आयोग ने ओबीसी को ऑर उडशुतुतुतुतु संखुतुः 1, 2, 3 और 4 में वभःजतुतुतु करने तथा 27% आरकुषण को कुरुडशः 2, 6, 9 और 10% में वभःजतुतुतु करने का प्रसुतुतुव दलतः ।
- इसने सभुी ओबीसी रकुऑरुड के डुरुण डऑःतुलुीकरण और ओबीसी डुरडःण डतुतुतु ऑरुतुतु करने की एक मःनकुीकृत डुरणःलुी की भी सफःारशः की ।

## ओबीसी आरकुषण की सुथतुतुतु:

- वर्ष 1953 में सुथःडतुतु कःलेलकर आयोग, राषुद्रीय सुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतु (SC) और अनुसुऑतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतु (ST) के अलःवः अन्य पछिडे वर्गुतु की पहऑःन करने वःलः पहलः आयोग थः ।

- मंडल आयोग की रिपोर्ट, 1980 में ओबीसी जनसंख्या 52% होने का अनुमान लगाया गया था और 1,257 समुदायों को पछिड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
  - इसने ओबीसी को शामिल करने के लिये मौजूदा कोटा, जो केवल एससी/एसटी के लिये था, को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने की सफारिश की।
- केंद्र सरकार ने OBC [अनुच्छेद 16 (4)] के लिये यूनियन सविलि पदों और सेवाओं में 27% सीटें आरक्षण की हैं। कोटा बाद में केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों [अनुच्छेद 15 (4)] में लागू किया गया।
  - वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को OBC के बीच क्रीमी लेयर (उन्नत वर्ग) को बाहर करने का निर्देश दिया।
- 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जो पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था।

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/extension-to-obc-sub-categorisation-commission-1>

